गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 168
दि. 17.10.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

आज, दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है: पीएम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया

मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला, आज श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है: प्रधानमंत्री

मुझे श्री शिवाजी स्पूर्ति केंद्र जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं: प्रधानमंत्री

आंध्र प्रदेश 'स्वाभिमान' और 'संस्कृति' की धरती है, साथ ही यह विज्ञान और नवाचार का केंद्र भी है: प्रधानमंत्री

आज, क्लीन एनर्जी से लेकर देश के कुल ऊर्जा उत्पादन तक, भारत हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रहा है: प्रधानमंत्री

आज देश में मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हो रहा है, हम गांवों से शहरों तक और शहरों से बंदरगाहों तक कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं: प्रधानमंत्री

आज भारत की और आंध्र प्रदेश की गति और संभावना को पूरी दुनिया देख रही है, गूगल आंध्र प्रदेश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने जा रही है: प्रधानमंत्री

हमारी सरकार का विजन है - नागरिक केंद्रित विकास, हम लगातार नए सुधारों के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बना रहे हैं: प्रधानमंत्रीये पहल पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी, औद्योगिक विकास को बढ़ावा

देंगी और नागरिकों के जीवन को आसान बनाएंगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन परियोजनाओं से कुरनूल और आसपास के क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी। (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अहोबिलम के भगवान नरसिंह स्वामी और महानंदी के श्री महानंदीश्वर स्वामी की वंदना की। उन्होंने मंत्रालयम के गुरु श्री राघवेंद्र स्वामी से सभी की भलाई के लिए आशीर्वाद भी मांगा।

द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम - "सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम्" का एक श्लोक का जाप करते हुए, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बारह ज्योतिर्लिंगों में, भगवान सोमनाथ और भगवान मल्लिकार्जुन का नाम आरंभ में एक साथ आता है। श्री मोदी ने कहा, "यह मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म दादा सोमनाथ की पावन धरती गुजरात में हुआ, बाबा विश्वनाथ की धरती काशी की सेवा का अवसर मिला और अब श्रीशैलम का आशीर्वाद मिल रहा है।" श्रीशैलम की अपनी यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री ने शिवाजी स्पूर्ति केंद्र में श्रद्धांजलि अर्पित की और मंच से छत्रपति महाराज को नमन किया। उन्होंने अल्लामा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे श्रद्धेय शैव संतों को नमन किया। उन्होंने श्री उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी गारू और श्री हरि सर्वोत्तम राव सहित महान स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रधानमंत्री ने राज्य की असीम क्षमता और इसके युवाओं की असीम क्षमताओं पर जोर देते हुए कहा, "आंध्र प्रदेश स्वाभिमान और समृद्ध संस्कृति की धरती होने के साथ-साथ विज्ञान और नवाचार का केंद्र भी है।" उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को सही दृष्टि और नेतृत्व की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, श्री चंद्रबाबू नायडू गारु और श्री पवन कल्याण गारु जैसे नेताओं के साथ, आंध्र प्रदेश के पास केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन के साथ-साथ दूरदर्शी नेतृत्व भी है।

पिछले सोलह महीनों में आंध्र प्रदेश में हुए तेज विकास पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों के तहत अभूतपूर्व प्रगति के बारे में बताते हुए, श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली और अमरावती मिलकर विकास को गति देने के लिए काम कर रहे हैं।

श्री मोदी ने दोहराते हुए कहा कि 2047 तक भारत निश्चित रूप से एक विकसित राष्ट्र होगा और 21वीं सदी भारत और उसके 140 करोड़ नागरिकों की है। उन्होंने सड़क, बिजली, रेलवे, राजमार्ग और व्यापार से संबंधित कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की घोषणा की। किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास के लिए ऊर्जा सुरक्षा को आवश्यक बताते हुए, प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली एक ट्रांसमिशन परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की, जो देश की ऊर्जा क्षमता को और बढ़ाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की केवीकेएस के सशक्तिकरण पर उच्चस्तरीय बैठक

श्री शिवराज सिंह ने KVKs के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आयु तथा अन्य लाभ के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश

सभी KVKs में समानता के लिए राज्यों, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के स्तर पर भी समुचित समाधान के लिए पहल करने के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दिए निर्देश

देशभर में 731 KVK है, जिनके नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उन्हें छोटे किसानों के हित में मजबूती देना आवश्यक- श्री शिवराज सिंह

,,

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि भवन, नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) को अधिक सशक्त और परिणामकारी बनाने की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि देशभर में वर्तमान में 731 डश्ड है, जिनके नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उन्हें छोटे किसानों के हित में मजबूती देना आवश्यक है। शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र किसानों तक पहुंच के लिए देशभर में कार्यरत सबसे प्रमुख माध्यम हैं, इनकी भूमिका तकनीकी प्रसार, प्रशिक्षण एवं कृषि नवाचारों को किसानों तक पहुँचाने में है। श्री शिवराज सिंह ने कहा कि डश्डर को सरकार की किसान हितैषी नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को किसानों की भलाई और उनकी जागरूकता के लिए उनके बीच पहुंचाना चाहिए। साथ ही, डश्डर इंटीग्रेटेड फार्मिंग और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के दिए मॉडल बनाकर कार्य करें।

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, व्यापार एवं तकनीकी सहयोग को रेखांकित किया

उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार एवं सेवा मंत्री महामहिम श्री गेराल्डो अल्कमिन से मुलाकात की। श्री अल्कमिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। दोनों नेताओं ने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रति आशा व्यक्त की। उन्होंने ऊर्जा सहयोग बढ़ाने, फार्मास्यूटिकल्स एवं रक्षा क्षेत्र में साझेदारी को प्रगाढ़ करने और अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की।

चर्चा में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटलीकरण जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

सीएम योगी ने प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए व डीआर की दरों में वृद्धि का दिया उपहार

लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर प्रदेश के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की दरों में वृद्धि का उपहार दिया है। अब प्रदेश के सभी पात्र 16.35 लाख कर्मचारियों एवं 11.52 लाख पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को 01 जुलाई, 2025 से 55% के स्थान पर 58% की दर से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं राहत का भुगतान माह अक्टूबर, 2025 से नकद रूप में किया जाए। व्यापक हित में लिए गए इस निर्णय से मार्च, 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1,960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत पहुंचाना और उनके जीवनस्तर में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इस निर्णय का लाभ सभी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्यप्रभारित कर्मचारी तथा यूजीसी वेतनमान के कर्मचारी शामिल हैं। यह निर्णय प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रति संवेदना और सम्मान का प्रतीक है। दीपावली का यह उपहार उनके जीवन में नई ऊर्जा, प्रसन्नता और समृद्धि लेकर आएगा।

ब्राजील के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री गेराल्डो अल्कमिन ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया; आयुर्वेद को स्वास्थ्य और ज्ञान का 5,000 वर्ष पुराना खजाना बताया

'निवारक और सतत स्वास्थ्य सेवा के लिए दुनिया को आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान की आवश्यकता है' : श्री गेराल्डो अल्कमिन

'अगर यह छोटी सी यात्रा न होती, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पीठ दर्द का उपचार एआईआईए में करवाता': श्री गेराल्डो अल्कमिन

(जीएनएस)।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) को आज ब्राजील संघीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री, महामहिम श्री गेराल्डो अल्कमिन का आतिथ्य सत्कार करने का विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुआ। श्री गेराल्डो अल्कमिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं।

इस अवसर पर महामहिम श्री गेराल्डो अल्कमिन ने पारंपरिक और एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालियों को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व की अत्यधिक सराहना की। उन्होंने कहा, "आयुर्वेद स्वास्थ्य और ज्ञान का 5,000 वर्ष पुराना खजाना है। मैं स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों के उपचार और समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में अद्भुत कार्य के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को बधाई देता हूँ।" उन्होंने यह भी कहा, "निवारक और सतत स्वास्थ्य सेवा के लिए दुनिया को आयुर्वेद के शाश्वत ज्ञान की आवश्यकता है।"

श्री गेराल्डो अल्कमिन ने आयुर्वेद की वैश्विक प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए कहा कि, "जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, और आयुर्वेद जैसी प्राकृतिक और निवारक स्वास्थ्य प्रणालियों की मांग भी बढ़ रही है। अगर यह छोटी यात्रा न होती, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पीठ दर्द का इलाज यहीं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में करवाता।"

श्री गेराल्डो अल्कमिन ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए भारत सरकार और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की टीम को भी धन्यवाद दिया और कहा, "मैं भारत में और विशेष रूप से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में मेरे और मेरे प्रतिनिधिमंडल के आतिथ्य सत्कार के लिए आभारी हूँ।"

महामहिम श्री गेराल्डो अल्कमिन के साथ उनकी पत्नी सुश्री मारिया लूसिया अल्कमिन और 14 अधिकारियों का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। उसमें भारत में ब्राजील के राजदूत महामहिम श्री केनेथ नोब्रेगा और ब्राजील स्वास्थ्य नियामक एजेंसी (एएनवीआईएसए) के निदेशक महामहिम श्री रोमिसन रोड्रिग्स और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने वाले सेना प्रमुखों/उप-प्रमुखों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की

(जीएनएस)।

संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान योगदानकर्ता देशों के सैन्य प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेने वाले सेना प्रमुखों/उप-प्रमुखों ने अपने जीवनसाथी के साथ आज (16, अक्टूबर 2025) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने देशों के सर्वोत्तम मूल्यों और लोकाचार के गौरवशाली प्रतिनिधि हैं, जो स्थायी शांति और समृद्धि के प्रति अपने राष्ट्रों के अनुभव, विशेषज्ञता और संकल्प का भंडार साथ लाए हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत महानगर पालिका के सर्टिफाइड ग्रीन बॉण्ड की मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेल रिंगिंग कर लिस्टिंग कराई

*** -: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-**

*** प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने इकोलॉजी व इकोनॉमी के बीच उम्दा संतुलन बनाए रखा है**

*** सूरत शहर तथा महानगर पालिका स्वच्छता एवं ग्रीन मोबिलिटी क्षेत्र में देशभर में आदर्श**

*** सूरत मनपा के 'म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड इश्यू' में वैश्विक निवेशकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रुचि बढ़ी है**

गांधीनगर, 16 अक्टूबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूरत महानगर पालिका के म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड की बेल रिंगिंग कर लिस्टिंग कराई। इस अवसर पर सूरत के महापौर श्री दक्षेश मावाणी भी उपस्थित थे।

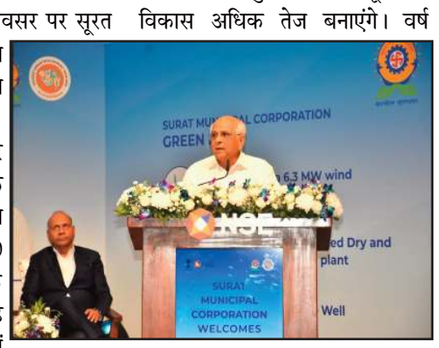

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरत महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से ग्रीन एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोगों को भागीदार बनाया गया है। सूरत महानगर पालिका के ग्रीन बॉण्ड का 8 गुना सबस्क्रिप्शन दशार्ता है कि निवेशकों ने ग्रीन बॉण्ड में निवेश करने में असाधारण उत्साह दिखाया है।

श्री पटेल ने कहा कि सूरत मनपा के दीर्घदृष्टि से युक्त आयोजन सूरत का विकास अधिक तेज बनाएंगे। वर्ष 2070 तक प्रधानमंत्री के नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में राज्य सरकार ने ग्रीन ग्रोथ तथा ग्रीन मोबिलिटी पर विशेष बल दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के बीच उम्दा संतुलन बनाए रखा है।

उन्होंने कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत 'वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर' के संदेश के साथ सदस्य देशों ने भी प्रधानमंत्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ को प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। यह संकल्प पूर्ण करने के लिए गुजरात ने 'विकसित गुजरात@2047' के रोडमैप सहित अनेक विकासोन्मुखी आयाम शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री सदैव जन भागीदारी के आग्रही रहे हैं। 'सरकारी पद्धति को प्रभावशाली बनाने' के ध्येय के साथ राज्य व केन्द्र सरकार के जन हितकारी प्रयास रहे हैं।

सम्पादकीय

नहीं सुलझ रही आईपीएस पूरन की आत्महत्या की गुत्थी

चंडीगढ़ में सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन वुमार की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर को 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन वुमार ने अपने चंडीगढ़ स्थित आवास पर खुद को गोली मार ली थी। इस खुदवुशी से पूरे राज्य में पुलिस महकमे में हड़वंप मच गया है। एक आईपीएस अधिकारी की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस को उनके पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ जिसमें उन्होंने हरियाणा पुलिस के डीजीपी समेत कई अधिकारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। आईपीएस पूरन वुमार की पत्नी आईएएस अमनीत वुमार हैं। जब पति ने खुदवुशी की उस वक्त अमनीत देश से बाहर गई हुई थीं। उन्होंने लौटकर पूरे मामले की जानकारी हासिल की। अब अमनीत वुमार और पूरा परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। परिवार ने आरोप लगाएं है कि पुलिस ने एफआईआर भी ठीक से नहीं लिखी और आरोपियों के नाम निश्चित जगह पर नहीं दिए गए है। परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। वाई पूरन वुमार की आत्महत्या के मामले में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर के पद से हटाने के लिए 31 सदस्यीय समिति ने राज्य सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेअल दिया है।

वाई पूरन वुमार की मौत के बाद पूरे प्रदेश में दलितों में भारी आव्रोश है। ऐसे में इस पर महापंचायत का आयोजन किया गया था जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकार डीजीपी के खिलाफ सख्त एक्शन ले और उन्हें पद से हटाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे हरियाणा में चंडीगढ़ में करीब 5000 सफाई कर्मचारी काम छोड़ देंगे। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार को कहा था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को भी आश्वासन दिया कि सरकार उनके साथ है। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की बात भी कही। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है जो मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने वाई पूरन वुमार की पत्नी को शोक संदेश भेजकर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि आज भी हुक्मरानों का पूर्वाग्रह से ग्रस्त पक्षपातपूर्ण रवैया बड़े से बड़े अधिकारी को भी सामाजिक न्याय की कसौटी से वंचित रखता है। 10 अक्टूबर को पूरन की पत्नी को भेजे गए पत्र में लिखा आपके पति वुमार के देहांत की खबर स्तब्ध करने वाली भी है और मन को व्यथित करने वाली भी। आपार मुश्किल की इस घड़ी में मेरी ओर से आपके अलावा पूरे परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। इस कठिन परिस्थिति में ईश्वर आपको धैर्य, साहस और संबल प्रदान करें। हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शनिवार को रोहतक के एसपी नरेन्द्र बिजारणिया को पद से हटा दिया है। सजा के तौर पर उन्हें अभी कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई। उधर शनिवार को 5वें दिन भी वाई पूरन वुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। चंडीगढ़ के गृहसचिव मनदीप बराड़ ने शनिवार को सुबह पूरन वुमार की पत्नी अमनीत वुमार के साथ मुलाकात की। इसके वुछ समय बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने वाई पूरन वुमार के राव को सेक्टर-16 अस्पताल में रखवा दिया। खबर आई है कि पत्नी अमनीत वुमार ने हल्की धाराएं लगाने पर आपत्ति जताई थी और सख्त धाराएं नहीं लगाने तक पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़ी थी। हरियाणा पुलिस ने रविवार को डीजीपी शत्रुजीत कपूर और तत्कालीन रोहतक एसपी नरेन्द्र बिजारणिया समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की नई धाराएं जोड़ी हैं, जिसके तहत उम्र वैद की सजा के साथ जुमार्ने का भी प्रावधान है। हम वाई पूरन वुमार को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और उम्मीद करते है कि उनके परिवार के साथ न्याय हो और इस पक्षपाती रवैया की कड़ी निंदा करते हैं।

अभी भी मौजूद है वैश्विक भुखमरी की भयावहता

खाने की कमी और वुपोषण के कारण दुनियाभर में लाखों लोग गंवा रहे जान

सुरक्षित जल और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना सुनिति करने के लिए बेहद जरूरी है कि दुनियाभर के देश पारंपरिक ज्ञान की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए विज्ञान और नवाचार के माध्यम से जल संसाधनों की कमी और जल सुरक्षा मुद्दों के नए समाधान ढूंढ़ने के गंभीर प्रयास करें।

खाने की कमी और वुपोषण के कारण दुनियाभर में लाखों लोग गंवा रहे जान दुनिया की आबादी तीव्र गति से बढ़ने के साथ-साथ विश्व में भूख की समस्या भी बढ़ती जा रही है।

कई ऐसे राष्ट्र हैं, जो इस समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। विश्वभर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्हें पेट भरने को दो समय का भोजन तक नसीब नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं, जिन्हें जिदा रहने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। पोषित और पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाने के कारण दुनिया की बड़ी आबादी वुपोषण की शिकार हो रही है। भोजन को एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार माना गया है लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी विड़म्बना है कि खाने की कमी और वुपोषण के ही कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग जान गंवा देते हैं।

भोजन, हवा और पानी के बाद तीसरी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरत हर किसी को पर्याप्त भोजन का अधिकार ही है।

चिताजनक स्थिति है कि दुनियाभर के किसान वैश्विक आबादी से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करते हैं किन्तु फिर भी भूख बनी रहती है।

वैश्विक भुखमरी को खत्म करने और सभी लोगों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष 16 अक्तूबर को 'विश्व खाद्य दिवस'

मनाया जाता है। दुनिया के करीब 150 सदस्य देश मिलकर यह दिवस मनाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के वैलेंडर में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला दिवस भी यही है। यह दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक भुखमरी से निपटना और पूरी दुनिया से उसे जड़ से खत्म करना है ताकि दुनिया का कोई भी इंसान भूखा और वुपोषित न रहे।

वृषि खाद्य प्रणाली परिवर्तन के लिए वैश्विक कार्रवाई को संगठित करते 'विश्व खाद्य दिवस' के लिए हर साल एक खास विषय निर्धारित किया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2025 का विषय है 'बेहतरभोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना', जो एक अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और खाद्यासुरक्षि त दुनिया के लिए वृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देता है।

एफएओ के अनुसार तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पिछले दशकों में मीठे पानी के संसाधनों में भी प्रति व्यक्ति 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और दशकों के खराब उपयोग व प्रबंधन, भूजल के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की उपलब्धता तथा गुणवत्ता तेजी से बिगड़ रही है।

एफएओ का कहना है कि मौजूदा समय में करीब 2.4 अरब लोग जल संकट वाले देशों में रहते हैं और इस अमूल्य संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है क्योंकि पानी की कमी संघर्ष का निरंतर बढ़ता कारण बनती जा रही है। पृथ्वी पर जल एक सीमित और असीम मूल्यवान ऐसा प्रावृतिक संसाधन है, जिसके बिना धरती पर भोजन और जीवन असंभव है। यही नहीं, विश्वभर में 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग अपनी आजीविका के लिए जलीय खाद्य प्रणालियों पर ही निर्भर हैं, जिनमें छोटे पैमाने के मछुआरे, मछली किसान, मछली प्रोसेसर और उनके आश्रित शामिल हैं, जो तटीय और अंतर्देशीय समुदायों की रीढ़ माने जाते हैं, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं और विश्वभर में संस्वृतियों को प्रभावित करते हैं।

दुनिया से भुखमरी को मिटाने के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, आर्थिक समस्याएं इत्यादि सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, बार-बार होने वाले मौसम के झटकों, संघर्षो, आर्थिक मंदी, असमानता और महामारी के कारण विश्व में करीब 733 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जिसका सर्वाधिक असर गरीब और कमज़ोर तबके पर पड़ता है, जिनमें से कई वृषि परिवार हैं। कोरोना महामारी के दौर के बाद लंबे समय से चल रहे रूस-यूोन और इजरायलफिलस्तीन के भीषण युद्ध जैसी विकट परिस्थितियां भी भूख की समस्या को कम करने के बजाय और विकराल बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इसीलिए इस समस्या को कम करने के लिए दुनियाभर में तेज गति से गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

संयुत्त राष्ट्र का कहना है कि भूख और वुपोषण लंबे समय तक चलने वाले संकटों से और बढ़ जाते हैं, जो संघर्ष, चरम मौसम की घटनाओं और आर्थिक झटकों के संयोजन से प्रेरित होते हैं।

आज दुनिया में करोड़ों लोग भूख से पीड़ित हैं और स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। एफएओ के मुताबिक विश्व में 2.8 बिलियन से भी ज्यादा लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और अस्वास्थ्यकर आहार ही सभी प्रकार के वुपोषण का प्रमुख कारण है। कमज़ोर लोगों को प्रायः मुख्य खाद्य पदार्थो या कम महंगे खाद्य पदार्थो पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जो अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं जबकि अन्य लोग ताज़े या विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से पीड़ित हैं, उन्हें स्वस्थ आहार चुनने के लिए जरूरी जानकारी की कमी है या फिर वे केवल सुविधा के लिए विकल्प चुनते हैं। दुनियाभर में प्रतिवर्ष हर 10 में से एक व्यत्ति दूषित भोजन के कारण बीमार हो जाता है और हर साल 4.2 लाख लोगों की मौत का कारण दूषित भोजन ही है, जिनमें करीब सवा लाख बच्चे भी होते हैं। संयुत्त राष्ट्र के 'खाद्य एवं वृषि संगठन' के अनुसार 2021 में दुनियाभर में 5 लाख लोगों की मौत भूख से ही हुई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर इतना अनाज पैदा नहीं हो रहा, जिससे दुनिया के हर व्यत्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके बल्कि सबसे बड़ी समस्या पोषणयुत्त आहार तक सभी की पहुंच और उपलब्धता है।

एफएओ का कहना है कि वर्तमान में मत्स्य पालन में हम करीब तीन हजार प्रजातियों का दोहन करते हैं जबकि इनमें से केवल 650 से वुछ अधिक प्रजातियों की ही खेती करते हैं।

एफएओ के मुताबिक इन जलीय पारिस्थितिक तंत्रों और उनके द्वारा समर्थित प्रजातियों का संरक्षण और सुरक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी ही नहीं है बल्कि पृथ्वी और इसके निवासियों की भलाई के लिए एक बड़ी आवश्यकता भी है। जलीय खाद्य पदार्थ भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपनी विविधता से जलीय खाद्य प्रणाली मानव के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिति करते हुए एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण खाद्य स्त्रोत बनती है। चिता का विषय है कि जीवनयापन के लिए आंशिक रूप से ही सही, जलीय खाद्य प्रणालियों पर निर्भर 60 करोड़ लोग प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण, अस्थिर प्रथाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पीड़ित हैं। ऐसे में न केवल जलीय खाद्य प्रणालियों की रक्षा करने की सख्त आवश्यकता है बल्कि लोगों को अधिक भोजन तथा अन्य बुनियादी वृषि उत्पाद पैदा करने के लिए कम पानी का उपयोग करने की आवश्यकता है।

बहरहाल, वैश्विक जल एवं जलीय खाद्य प्रणालियों की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया में मौजूदा जल चुनौतियों से निपटने के लिए अब लोगों द्वारा वृषि-खाद्य प्रणालियों में जल के वुशल उपयोग को सुनिति करने की बड़ी जरूरत महसूस की जाने लगी है।

सुरक्षित जल और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना सुनिति करने के लिए बेहद जरूरी है कि दुनियाभर के देश पारंपरिक ज्ञान की शक्ति का पूर्ण उपयोग करते हुए विज्ञान और नवाचार के माध्यम से जल संसाधनों की कमी और जल सुरक्षा मुद्दों के नए समाधान ढूंढ़ने के गंभीर प्रयास करें। मौजूदा जल चुनौतियों से निपटने के लिए हमें वृषि खाद्य प्रणालियों में प्रभावी जल उपयोग सुनिति करने और अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के सुरक्षित तरीके खोजने के साथ-साथ जल और जलीय खाद्य प्रणालियों की सुरक्षा भी सुनिति करनी होगी तथा जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मांग के मद्देनजर सभी के लिए किफायती पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए दुनिया के समक्ष मौजूद खाद्य चुनौतियों का मिलकर समाधान करना होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
योगेश वुमार गोयल विश्व खाद्य दिवस पर विशेष

हमारा लक्ष्य आयुर्वेद आहार को वैश्विक पोषण का अभिन्न अंग बनाना है: केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

आयुर्वेद आहार सूची स्टार्टअप्स को सशक्त बनाएगी और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से निपटेगी: सचिव, आयुष मंत्रालय

मंत्रालय और एफएसएसएआई ने आयुर्वेद-आधारित पोषण को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाया

(जीएनएस)।

विश्व खाद्य दिवस 2025 "बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना" थीम के तहत मनाया जा रहा है और ऐसे समय में आयुष मंत्रालय 'आयुर्वेद आहार' जैसी अभूतपूर्व पहलों के माध्यम से एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ पृथ्वी को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहरा रहा है। 'आयुर्वेद आहार' यानी भारत का अनूठा खाद्य दर्शन जो संतुलन, कल्याण और प्रकृति में निहित है।

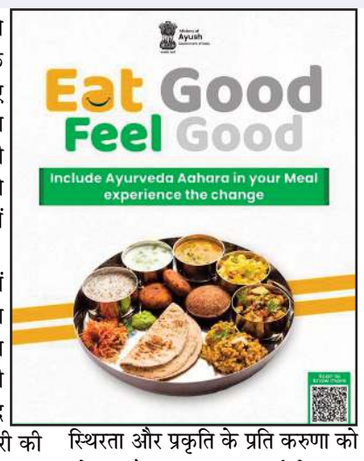

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने आयुष मंत्रालय के परामर्श से, हाल ही में श्रेणी 'ए' के अंतर्गत आयुर्वेद आहार उत्पादों की एक सूची जारी की है जो प्रामाणिक आयुर्वेदिक आहार तैयारियों के लिए पहला व्यापक संदर्भ ढांचा प्रदान करती है। प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित इस सूची से आयुर्वेद-आधारित पोषण में वृद्धि, गुणवत्ता और वैश्विक विश्वास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद आहार के महत्व पर कहा कि इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का विषय भारत के पारंपरिक ज्ञान से गहराई से मेल खाता है। आयुर्वेद आहार केवल भोजन नहीं है, यह एक ऐसा दर्शन है जो स्वास्थ्य, स्थिरता और प्रकृति के प्रति करुणा को जोड़ता है। एफएसएसएआई के साथ अपने सहयोग के माध्यम से, हमारा लक्ष्य आयुर्वेद आहार को वैश्विक पोषण का एक अभिन्न अंग बनाना है और यह सुनिश्चित करना है कि बेहतर खाद्य पदार्थ एक बेहतर, रोगमुक्त भविष्य का निर्माण करें।

एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित आयुर्वेद आहार नियम, भारत के पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान को आधुनिक खाद्य सुरक्षा मानकों के साथ एकीकृत करने में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। इसी आधार पर, अंतिम उत्पाद सूची जारी करने से यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं और खाद्य व्यवसायों, दोनों के पास शास्त्रीय आयुर्वेदिक ज्ञान पर आधारित स्पष्ट और प्रमाणित संदर्भ उपलब्ध हों।

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुर्वेद-आधारित खाद्य प्रणालियों में बढ़ती वैश्विक रुचि समग्र पोषण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। आयुर्वेद आहार ढांचा, जो अब निश्चित सूची द्वारा सुदृढ़ हुआ है, निमार्ताओं के लिए स्पष्टता और उपभोक्ताओं में विश्वास लाता है। हम इसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में देखते हैं जहां आयुर्वेद का ज्ञान आहार और जीवनशैली से संबंधित विकारों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने में मदद कर सकता है जो गैर-संचारी रोगों का कारण बनते हैं।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), जयपुर के प्रोफेसर अनुपम श्रीवास्तव ने इस पहल के वैज्ञानिक और शैक्षिक आयाम पर कहा कि आयुर्वेदिक आहार सिद्धांतों को मुख्यधारा की पोषण नीति में शामिल करके, भारत दुनिया को दिखा रहा है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान स्थायी और सचेतन आहार पद्धतियों का मार्गदर्शन कर सकता है। आयुष और एफएसएसएआई के बीच सहयोग बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए 'हाथ से हाथ मिलाकर' काम करने का एक उदाहरण है।

भारत की पारंपरिक खाद्य प्रणालियां—जिनका प्रतीक विविध और संतुलित भारतीय थाली है—अब अपनी पोषण संबंधी और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए विश्व स्तर पर पहचानी जा रही हैं। आयुर्वेद के प्राचीन आहार ज्ञान से प्रेरित ये खाद्य मॉडल मौसमी भोजन, स्थानीय स्रोतों से प्राप्त खाद्य सामग्री और सोच-समझकर उपभोग पर जोर देते हैं—जो स्थायी खाद्य प्रणालियों के वैश्विक आह्वान के साथ पूरी तरह मेल खाता है।

जैसे-जैसे दुनिया भोजन के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, भारत संतुलन के आधार के रूप में खड़ा है जो यह दर्शाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर एक मजबूत और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आयुष मंत्रालय, एफएसएसएआई और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से, आयुर्वेद आहार को पोषण, स्थिरता और वैश्विक कल्याण का पर्याय बनाने के अपने मिशन में अडिग है।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद 17 अक्टूबर को देहरादून में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे

उत्तराखंड भारत के लिए प्री-समिट - एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा, जो उत्तरदायी और समावेशी एआई विकास पर केंद्रित होगा

यह कार्यक्रम नीति निमार्ताओं, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा ताकि डिजिटल इंडिया विजन के साथ संयोजित नवोन्मेषण, शासन और उद्यमिता के माध्यम से डिजिटल उत्तराखंड विजन को आगे बढ़ाया जा सके

(जीएनएस)।

उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के इंडिया एआई मिशन के सहयोग से 17 अक्टूबर, 2025 को देहरादून के होटल रमाडा में उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का आयोजन कर रही है। यह आयोजन 19-20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले इंडिया-एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का एक प्री-समिट कार्यक्रम है।

इस कार्यक्रम में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (एमओएस) श्री जितिन प्रसाद के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026, विकासशील देशों (ग्लोबल साँउथ) में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई फोरम है, जो वैश्विक एआई एजेंडे को आकार देने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाता है। "सभी के लिए एआई" के राष्ट्रीय विजन पर आधारित, अगले वर्ष के वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन से पूर्व यह शिखर सम्मेलन सामाजिक समावेशन, नवाचार और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है।

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों या सूत्रों पर आधारित है: लोग, ग्रह और प्रगति, जो यह निर्धारित करते हैं कि एआई को मानवता की सेवा कैसे करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए और समावेशी विकास को कैसे गति देनी चाहिए। इन मार्गदर्शक सूत्रों को सात चक्रों या

विषयगत कार्य समूहों के माध्यम से आगे क्रियान्वित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक एआई के वैश्विक प्रभाव के एक महत्वपूर्ण आयाम पर केंद्रित है। ये सूत्र और चक्र मिलकर एक सुसंगत ढांचा प्रदान करते हैं जो संवाद को आकांक्षात्मक प्रतिबद्धताओं से मापनीय परिणामों की ओर ले जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि एआई के लाभ विश्व भर में समान रूप से प्राप्त हों।

भारत-एआई इम्पैक्ट समिट के तत्वावधान में आयोजित उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025, राज्य को ज़िम्मेदार और समावेशी एआई-संचालित विकास में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है। प्री-समिट कार्यक्रम नीति निमार्ताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि एआई उत्तराखंड में सतत विकास को कैसे गति दे सकता है और नवाचार को बढ़ावा देकर, शासन में सुधार लाकर और ज़िम्मेदार और समावेशी एआई को अपनाकर उद्यमिता को सशक्त बनाकर राज्य के डिजिटल उत्तराखंड विजन को आगे बढ़ा सकता है। भारत के डिजिटल परिवर्तन एजेंडे और भारत-एआई मिशन के अनुरूप, यह शिखर सम्मेलन विश्वास, नैतिकता और समावेशिता पर आधारित, उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में परिवर्तन लाने वाले अत्याधुनिक एआई अनुप्रयोगों और उद्यमशीलता पहलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें आईआईएम काशीपुर और एसटीपीआई देहरादून द्वारा समर्थित अग्रणी एआई-आधारित स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी, साथ ही राज्य के आईटी रोडमैप और एआई गवर्नेंस विजन पर मुख्य सत्र भी आयोजित किए जाएँगे, जो सतत, नवाचार-आधारित विकास के लिए एक दूरदर्शी मार्ग तैयार करेंगे।

भारत के बारे में - एआई इम्पैक्ट समिट 2026

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित, भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026, 19-20 फरवरी, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक मंच समावेशी विकास, स्थिरता और समान प्रगति को बढ़ावा देने में एआई की परिवर्तनकारी भूमिका को प्रदर्शित करेगा। यह शिखर सम्मेलन एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जहां एआई मानवता की सेवा करे, समावेशी विकास को आगे बढ़ाए, सामाजिक विकास को बढ़ावा दे और ऐसे नवाचारों को बढ़ावा दे जो पृथ्वी की रक्षा करें।

तीन सूत्र

शिखर सम्मेलन तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों या सूत्रों पर आधारित होगा:

लोग: एआई को अपनी समस्त विविधता में मानवता की सेवा करनी चाहिए, सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना चाहिए, गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वंचित न रह जाए। फोकस क्षेत्रों में एआई-सक्षम विश्व में मानव विकास, बहुभाषी और सुलभ प्रणालियां और सुरक्षित एवं विश्वसनीय तैनाती शामिल हैं।

ग्रह: एआई का विकास और तैनाती संसाधन-कुशल होनी चाहिए और साथ ही जलवायु लचीलापन, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक खोजों में भी तेजी लाई जानी चाहिए। एआई को विश्व की प्राकृतिक प्रणालियों और संसाधनों तथा वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ संयोजित होना चाहिए।

प्रगति: एआई के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, डेटासेट, कंप्यूट और मॉडल की सुविधा का लोकतंत्रीकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शासन और कृषि में एआई को लागू किया जाना चाहिए।

सात चक्र

सूत्रों को सात चक्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। ये बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र हैं, जिन्हें ठोस परिणाम देने के लिए डिजाइन किया गया है:

मानव पूंजी - रोजगार, कौशल विकास और कार्यबल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करें।

साक्षरता, पुनः कौशल विकास और भविष्य के कौशलों तक समान पहुंच के लिए वैश्विक ढांचे विकसित करें।

ट्राई ने स्पैम और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दों पर नियामकों की 9वीं संयुक्त समिति (जेसीओआर) की बैठक बुलाई

डिजिटल सहमति प्राप्ति के लिए पायलट प्रोजेक्ट पटरी पर, 1600-सीरीज कॉल अपनाने पर जोर, सभी यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके और एसएमएस में भेजे गए कॉलबैक नंबरों को अनिवार्य रूप से श्वेतसूची में डालना, संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करना और उन्नत पीई-एंड सुरक्षा उपाय

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज नई दिल्ली स्थित ट्राई मुख्यालय में नियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) की 9वीं बैठक आयोजित की।

इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग (डीओटी), गृह मंत्रालय (एमएचए), उपभोक्ता कार्य मंत्रालय (एमओसीए) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के अधिकारी भी शामिल हुए।

उद्योग प्रतिनिधियों के साथ एक सत्र भी आयोजित किया गया जिसमें उपभोक्ता सशक्तिकरण, विश्वास बढ़ाने और डिजिटल संचार चैनलों के माध्यम से किए गए स्पैम और धोखाधड़ी के खिलाफ उपयोगकताओं की सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पहलों पर गूगल, मेटा, जीएसएमए और सीओएआई के साथ चर्चा की गई।

जेसीओआर समिति ने डिजिटल सहमति प्राप्ति के लिए पायलट परियोजना की प्रगति की समीक्षा की, जिसे 11 (ग्यारह) नामित बैंकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, और ट्राई और आरबीआई द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। पायलट परियोजना संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है और फरवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। समिति ने 22 जुलाई 2025 को आयोजित 8वीं जेसीओआर बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की और 1600-श्रृंखला नंबरिंग योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा, छोटे यूआरएल का दुरुपयोग, एसएमएस में भेजे गए यूआरएल/ ओटीटी लिंक/ एपीके/ कॉलबैक नंबरों की अनिवार्य श्वेतसूचीकरण और ब्लैकलिस्टेड संस्थाओं के विवरण के प्रकाशन सहित नए एजेंडा पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और डिजिटल संचार इकोसिस्टम की अखंडता को बढ़ाने के लिए विनियामक और तकनीकी उपायों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

विचार-विमर्श के मुख्य परिणाम

समिति ने डिजिटल सहमति प्राप्ति के पायलट प्रोजेक्ट को फरवरी 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। समिति ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्रों में 1600-श्रृंखला संख्या योजना में स्थानांतरण के लिए एक चरणबद्ध समय-सीमा पर सहमति व्यक्त की। क्षेत्रीय नियामकों ने सहमत समय-सीमाओं के प्रति अपने समर्थन का आश्वासन दिया।

समिति ने 1600 श्रृंखला अधिदेश से लघु-स्तरीय वित्तीय/व्यावसायिक संस्थाओं के लिए विभेदक व्यवहार पर भी चर्चा की। ट्राई इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

सदस्यों ने वाणिज्यिक संचार में प्रयुक्त सभी यूआरएल, ओटीटी लिंक, एपीके और कॉलबैक नंबरों को अनिवार्य रूप से श्वेतसूची में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। ट्राई ने सदस्यों को इन संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के अपने अभियान से अवगत कराया, जिसके लिए स्वीकृत एसएमएस टेम्प्लेट में इन लिंक्स को टैग किया जाएगा, जिसके लिए अन्य सदस्यों के गहन समर्थन की आवश्यकता है।

सदस्यों ने इस प्रयास के लिए अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

समिति ने इस बात पर चर्चा की कि ट्राई और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) अपनी-अपनी वेबसाइटों पर स्पैमिंग गतिविधियों के लिए काली सूची में डाली गई संस्थाओं की सूची प्रकाशित करने पर विचार कर सकते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

आंबलियासन-विजापुर रेलखंड का गेज परिवर्तन कार्य पूर्ण, संरक्षा निरीक्षण जारी

42.32 किमी लंबा खंड अब ब्रॉड गेज में परिवर्तित, 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को हो रहा है संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के आंबलियासन-विजापुर रेलखंड (42.32 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह रेलखंड वर्ष 1902 में मीटर गेज लाइन के रूप में प्रारंभ हुआ था और अब इसका ब्रॉड गेज में परिवर्तन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब यह खंड यात्रियों के लिए आधुनिक एवं सुरक्षित परिचालन हेतु तैयार है। इस खंड का संरक्षा निरीक्षण (रीं३८ कल्ल२स्री३ड्डल्ल) रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र), पश्चिम रेलवे श्री ई. श्रीनिवास द्वारा 16 एवं 17 अक्टूबर 2025 को किया जा रहा है।

पिछले दो महीनों में रेल संरक्षा आयुक्त (उफ्र) द्वारा लगभग 100 किमी खंडों का निरीक्षण किया जा चुका है, जिनमें हाल ही में सम्पन्न हिम्मतनगर-खेडब्रह्मा रेलखंड (54.83 किमी) का उफ्र निरीक्षण भी शामिल है। साथ ही, विजापुर-आदराज मोती रेलखंड (39.85 किमी) का गेज परिवर्तन कार्य भी शीघ्र पूर्ण होने की दिशा में है, जिसका संरक्षा निरीक्षण आगामी दिनों में किया जाएगा।

दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को निरीक्षण के प्रथम दिवस पर रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा आंबलियासन से कूकरवाड़ा तक कुल 26.61 किलोमीटर लंबाई के खंड का मोटर ट्रॉली के माध्यम से विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आंबलियासन स्टेशन से निरीक्षण प्रारम्भ किया गया तथा सिग्नल एवं इंटरलॉकिंग पैनल की कार्यप्रणाली की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, फ्चइ नंबर 98अ एवं 79इ पर ऊँचाई माप (ल्र्ीं३ ं्रॠ) एवं जल निकासी (ठ्र्ल्लॅ अ११ल्लॅील्ल३) की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।

आगे लांघंज स्टेशन तथा गोझारिया स्टेशन का भी संरचनात्मक एवं सिग्नलिंग निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही लेवल क्रॉसिंग नंबर 69, 77, 78 एवं 88, मेजर ब्रिज नंबर 85अ एवं 97 का निरीक्षण किया गया। सभी स्थलों पर मोटर ट्रॉली द्वारा ट्रैक संरचना, पुल, सिग्नलिंग व्यवस्था एवं सुरक्षा उपायों की गहन समीक्षा की गई।

निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (उफ्र), पश्चिम रेलवे, श्री वेद प्रकाश, मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण एवं ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

परियोजना के अंतर्गत इस खंड में कुल 02 मेजर ब्रिज, 51 माइनर ब्रिज तथा 45 नए रोड अंडर ब्रिज (फ्वइर) का निर्माण किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु रेलवे लाइन को लेवल क्रॉसिंग के समीप फेंसिंग द्वारा संरक्षित किया गया है तथा इस खंड पर कुल 04 लेवल क्रॉसिंग्स हैं।

ब्रॉड गेज ट्रैक में 60 किलोग्राम के नए रेल पैनल बिछाए गए हैं। आंबलियासन एवं विजापुर स्टेशनों को स्टैंडर्ड-क्क इंटरलॉकिंग सिस्टम और मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग (टअउछर) से सुसज्जित किया गया है, जिससे ट्रेनों के संचालन की सुरक्षा एवं दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

यह नया ब्रॉड गेज खंड देश के प्रमुख रेलवे नेटवर्क से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएगा, जिससे यात्रियों को अधिक तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना से उत्तरी गुजरात के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे यात्रा समय में कमी, व्यापार एवं कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था में सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।

इस खंड के चालू होने से विजापुर क्षेत्र के प्रसिद्ध गेहूँ, आलू एवं तेल उत्पादों की आपूर्ति देशभर में अधिक सुगमता से हो सकेगी, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा तथा क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्राप्त होगी।

संरक्षा निरीक्षण के अंतिम दिन, 17 अक्टूबर 2025 को इंजन स्पीड ट्रायल 120 किमी/घंटा की गति से किया जाएगा, जिसके पश्चात इस खंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किए जाने की दिशा में आगे की प्रक्रिया आरंभ होगी।

पश्चिम रेलवे की यह परियोजना

पश्चिम रेलवे चलायेगी अहमदाबाद-शेखपुरा के बीच स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा आगामी दिवाली त्योहार के मद्देनजर यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-शेखपुरा के बीच स्पेशल ट्रेन विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इन स्पेशल ट्रेन का विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09463/09464 अहमदाबाद-शेखपुरा-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन विशेष किराए पर (04 फेरे)

ट्रेन संख्या 09463 अहमदाबाद-शेखपुरा स्पेशल अहमदाबाद से 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) और 23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार) को दोपहर 15:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा तीसरे दिन सुबह 04:00 बजे शेखपुरा पहुचेंगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09464 शेखपुरा-अहमदाबाद स्पेशल शेखपुरा से 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार) और 25 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को सुबह 06:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा दूसरे दिन साँय 20:00 बजे अहमदाबाद पहुचेंगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन नदियाद, आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मकसी, संत हिरदारम नगर, बिना, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिक्की, मिजार्पुर, पं. दिन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑनसोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, तिलैया, नवादा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2 टियर, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09463 की बुकिंग 17 अक्टूबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने पंजाब में परियोजनाओं की समीक्षा की; प्रौद्योगिकी आधारित मत्स्य पालन, कौशल विकास और विविधीकृत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का आग्रह किया

(जीएनएस)।

डॉ. अभिलक्ष लिक्खी, सचिव, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय, भारत सरकार ने फतेहगढ़ साहिब जिले का दौरा किया।और मछली किसानों और मत्स्य उद्यमियों के साथ बातचीत की ताकि उनके मुद्दों और चुनौतियों को समझा जा सके,विशेष रूप से रीसक्युर्लेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और झींगा पालन में। फतेहगढ़ साहिब जिले के बस्सी पठाना के दलुतपुर गांव में आधुनिक आरएएस सुविधाओं के दौरे के दौरान, डॉ. लिखी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत चल रही मत्स्य पालन परियोजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। उन्हें स्थानीय किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन रीतियों के बारे में जानकारी दी गई, जिन्होंने बंजर भूमि को उत्पादक जलीय कृषि केंद्रों में सफलतापूर्वक बदल दिया है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा हुए हैं। लगभग 35-40 प्रगतिशील मछली किसानों ने अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा करते हुए बातचीत में भाग लिया। उन्होंने प्रमुख मत्स्य पालन कार्यक्रमों के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के विकास, नवाचार और क्षमता वृद्धि के माध्यम से आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियों को समर्थन देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस यात्रा ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में खारे पानी की जलीय कृषि को सरकार की प्राथमिकता पर भी जोर दिया। ये क्षेत्र, जो अक्सर कृषि क्षेत्रों से खारे पानी के प्रवेश से प्रभावित होते हैं, जलीय कृषि के माध्यम से भूमि-उपयोग अनुकूलन के अनूठे अवसर प्रस्तुत करते हैं।

पृष्ठभूमि -

भारत के अंतदेर्शीय जल संसाधनों की क्षमता अभी भी विशाल और काफी

हद तक अप्रयुक्त है। 1.95 लाख किलोमीटर लंबी नदियों और नहरों, 6.06 लाख हेक्टेयर खारे पानी, 3.65 लाख हेक्टेयर बील और ऑक्सबो झीलों, 27.56 लाख हेक्टेयर तालाबों और पोखरों, और 31.53 लाख हेक्टेयर जलाशयों के साथ, सतत अंतदेर्शीय मत्स्य पालन विकास की अपार संभावनाएँ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अंतदेर्शीय मत्स्य पालन को इस क्षेत्र के लिए अपनी रणनीतिक दृष्टि के केंद्र में रखा है। भारत का अंतदेर्शीय मत्स्य पालन क्षेत्र राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन की आधारशिला के रूप में उन्नति की है, जो कुल उत्पादन में 75% का योगदान देता है। इस क्षेत्र में शीत जल मत्स्य पालन और तिलापिया और पंगेसियस जैसी प्रजातियों को शामिल करके प्रजातियों के विविधीकरण सहित कई गतिविधियाँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अंतदेर्शीय मत्स्य उत्पादन 139.07 लाख मीट्रिक टन रहा। 2013-14 और 2024-25 के बीच, अंतदेर्शीय मत्स्य उत्पादन में 142% की वृद्धि हुई, जो 61 लाख टन से बढ़कर 147.37 लाख टन हो गया। इस विस्तार ने भारत के समग्र राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन को 195 लाख टन तक पहुँचा दिया है, जो इसी अवधि की तुलना में 104% की वृद्धि दशार्ता है। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत, अंतदेर्शीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षमता का दोहन करने के लिए "प्रौद्योगिकी संचार और अपनाने" में देश भर में ₹3,300 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 12,000 आरएएस इकाइयाँ, 4,000 बायोफ्लोक प्रणालियाँ, 59,000 पिंजरे और 561 हेक्टेयर बाड़े स्थापित किए गए हैं। इन उपायों ने राष्ट्रीय औसत जलीय कृषि उत्पादकता को 4.77 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है।

पंजाब ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें 72 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन सहित 187 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। राज्य के लिए मछली उत्पादन का लक्ष्य 2.21 लाख टन है, जिसका वास्तविक उत्पादन 2023-24 में 1.84 लाख टन तक पहुंच जाएगा। पंजाब में, आधुनिक जलीय कृषि प्रथाओं ने पिछले पांच वर्षों में किसानों की आय में लगभग 500 करोड़ रुपये जोड़े हैं, 2020-21 से मछली उत्पादन में 35,000 टन से अधिक की वृद्धि हुई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए बंजर भूमि का उत्पादक उपयोग करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 263.80 हेक्टेयर को कवर करने वाले खारे पानी के जलीय कृषि परियोजना प्रस्तावों को 36.93 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है पंजाब के मुक्तसर साहिब और हरियाणा के सिरसा ज़िले में खारे पानी के जलीय कृषि समूहों की स्वीकृति और अधिसूचना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उन्नति की है। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने हरियाणा के सिरसा ज़िले, पंजाब के मुक्तसर साहिब ज़िले और राजस्थान के चुरू ज़िले में खारे पानी के समूहों के विकास के लिए भी अधिसूचना जारी की है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर के बीच चलाएगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दिवाली एवं छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण इस प्रकार हैः

1. ट्रेन संख्या 04826/04825 बांद्रा टर्मिनस - जोधपुर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 04826 बांद्रा टर्मिनस - जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से 21:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:45 बजे जोधपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04825 जोधपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक बुधवार को जोधपुर से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 18:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, फुलेरा, नवा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, रेन, मेड़ता रोड और गोटन स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04826 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर 18 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा सन्तोष कुमार झा 'राजभाषा सम्मान' से अलंकृत

मुंबई, 16 अक्टूबर। विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अधिवेशन के दूसरे दिन नैनी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में स्थित जगतपिता ब्रह्मदेव धर्मशाला, देवरख में 'हिन्दी संगोष्ठी' एवं 'सम्मान समारोह' आयोजित किया गया, जिसमें कोंकण रेलवे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सुप्रसिध्द कवि सन्तोष कुमार झा को उनके नेतृत्व में किये जा रहे उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 'राजभाषा सम्मान- 2024' से गौरवान्वित किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त डॉ. सुरेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि संस्कृत और हिन्दी एक ही सांस्कृतिक परंपरा की भाषाएँ हैं। अंग्रेजी जानना आवश्यक है, पर हिन्दी की कीमत पर नहीं। विशिष्ट अतिथि डॉ. एन. बी.

विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज द्वारा प्रदत्त 'राजभाषा सम्मान' और प्रशस्ति पत्र के साथ कोंकण रेलवे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संतोष कुमार झा।

सिंह 'हरियाली गुरु' रहे। इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। उसी क्रम में, कोंकण रेलवे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रसिध्द कवि श्री सन्तोष कुमार झा को उनके नेतृत्व में किये जा रहे उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु 'राजभाषा सम्मान-2024' से गौरवान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि श्री झा के चार काव्य संग्रह 'उन्मुक्त', 'सूरज का वारिस', 'फूल, कलम और बंदूक' तथा 'स्याही का सिपाही' प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य सम्मानित साहित्यकारों में डॉ. वंदना अग्निहोत्री, डॉ. सीमा वर्मा, डॉ. विजयलक्ष्मी, रजनी प्रभा, फरहत, राणा प्रताप सहित अनेक विद्वान शामिल रहे। मंच संचालन डॉ. सीमा वर्मा एवं रश्मि चौबे ने किया तथा डॉ. गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के हम्पी में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की

कार्यक्रम में पीएमआईएस के माध्यम से युवाओं में बदलाव की सफलता की कहानियां साझा की गईं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रशिक्षुओं को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनके समर्पण को सराहा

(जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त और कॉपोर्रेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर, 2025 को कर्नाटक के हम्पी में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। इस सत्र में इंफोसिस, एमएसपीएल, आईबीएम, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स, एचएएल, एनएमडीसी और हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस सहित प्रमुख भागीदार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पूरे कर्नाटक से 60 से अधिक प्रशिक्षु एक साथ आए।

बातचीत के दौरान श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रशिक्षुओं से बातचीत की और पीएमआईएस के तहत उनके अनुभव और आकांक्षाओं को सुना। उन्होंने प्रशिक्षुओं से पूछा कि इस योजना में शामिल होने के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया। इंटर्नशिप के दौरान प्रशिक्षुओं के सीखने और कौशल विकास के उनके अनुभव पर भी चर्चा की गई। पीएमआईएस प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षुओं को उनके पेशेवर सफर के लिए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया।

इसके अलावा, अपनी इंटर्नशिप के दौरान असाधारण प्रदर्शन करने वाले कुछ प्रशिक्षुओं को उनकी संबंधित कंपनियों द्वारा पूर्णकालिक पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने उपलब्धियों के लिए प्रशिक्षुओं को बधाई दी और उनके प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की।

उन्होंने प्रशिक्षुओं की लगन की सराहना की और आज के बदलते कार्यस्थल में अनुकूलनशीलता के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा, " यह जानकर खुशी हो

रही है कि यह इंटर्नशिप व्यक्तित्व विकास में किस तरह योगदान दे रही है। प्रशिक्षु काम के मूल पहलुओं को सीख रहे हैं और साथ ही संचार की बाधाओं को दूर करने जैसे अन्य कौशल भी निखार रहे हैं। "

इस कार्यक्रम में पीएमआईएस के माध्यम से युवाओं में आए बदलाव की उल्लेखनीय कहानियां प्रदर्शित की गईं।

ऐसी ही एक कहानी आंध्र प्रदेश के कडप्पा के कलुवा हरि कृष्ण की है, जिन्होंने आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटर्नशिप पूरी करने के बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में पूर्णकालिक नौकरी हासिल की। एक किसान और गृहिणी के बेटे हरि ने अपनी यात्रा को "सचमुच परिवर्तनकारी" बताया। उन्होंने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की कि उन्हें मंत्री महोदया व्यक्तिगत रूप से अपना ऑफर लेटर दें, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।

आंध्र प्रदेश में चित्तूर की एक अन्य प्रशिक्षु आर. लक्ष्मी प्रसन्ना ने बताया कि कैसे इंफोसिस में शामिल होने के बाद पीएमआईएस ने उनके लिए नए दरवाजे खोले। कृषि पृष्ठभूमि से आने वाली लक्ष्मी प्रसन्ना ने कहा कि इस इंटर्नशिप ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और कॉपोर्रेट जगत से जुड़ने का मौका दिया।

इसी तरह, केरल की हनीवेल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लैब प्राइवेट लिमिटेड में एम्बेडेड इंजीनियर इंटर्न सुश्री गौरी एच ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की। एकल मां की बेटी होने के नाते, उन्होंने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, लेकिन अपने क्षेत्र में उन्हें सीमित अवसर मिले। उन्होंने कहा कि पीएमआईएस ने उन्हें उस करियर में आगे बढ़ने में मदद की जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। केंद्रीय मंत्री ने उनकी यात्रा की सराहना करते हुए कहा, "मैं गौरी की सकारात्मकता और दृढ़ता से प्रभावित हूं। उनकी जैसी कहानियां ही पीएमआईएस के पीछे के सच्चे इरादे और भावना को दशार्ती हैं।"

इस बातचीत में पीएमआईएस के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित किया गया तथा विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को विकसित करने में सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस), प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहलों के पैकेज का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पांच वर्षों की अवधि में भारतीय युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर प्रदान करना है। पीएमआईएस का उद्देश्य 21-24 वर्ष की आयु के उन युवाओं को लक्षित करना है जो वर्तमान में किसी भी पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम या रोजगार में नामांकित नहीं हैं। यह उन्हें देश भर की शीर्ष कंपनियों में सशुल्क इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक इंटर्नशिप प्रदान करना है और इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। अभी इस योजना का प्रायोगिक चरण चल रहा है।

भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया की विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के 78वें सत्र में स्वस्थ वृद्धावस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के को शामिल किया गया है, जिससे 6 करोड़ बुजुर्गों को अस्पताल में कैशलेस देखभाल मिलेगी : श्रीमती अनुप्रिया पटेल

भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक देखभाल का एकीकरण मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया

आह्वान केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने 13-15 अक्टूबर, 2025 के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया की विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के कोलंबो में आयोजित 78वें सत्र के मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान, विचार-विमर्श "मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से स्वस्थ वृद्धावस्था" विषय पर केन्द्रित था।

भारत ने बुजुर्गों के लिए एक व्यापक और जन-केन्द्रित प्रणाली पर आधारित, मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से स्वस्थ वृद्धावस्था को बढ़ावा देने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

श्रीमती पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 153 मिलियन नागरिकों के साथ, भारत एक बड़े जनसांख्यिकीय परिवर्तन का सामना कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बुजुर्गों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समान, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों, सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण

कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम (एनपीएचसीई), जो अब 92 प्रतिशत जिलों में चल रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवारक, प्रोत्साहन, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के भारत के प्रयासों की आधारशिला है। यह कार्यक्रम परिवारों और समुदायों में सम्मानजनक वृद्धावस्था को सक्षम बनाने के लिए संरचित देखभालकर्ता प्रशिक्षण के साथ-साथ घर, समुदाय और सुविधा-आधारित हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है।

वृद्धजनों की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत करते हुए, आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, इसके अंतर्गत लाने के लिए किया गया है। इससे 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वृद्धजन लाभान्वित होंगे, और उन्हें सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस अस्पताल देखभाल प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय मंत्री ने दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केन्द्रों (एनसीए) की स्थापना पर भी प्रकाश डाला—एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई और देश भर में 17 क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो नैदानिक उत्कृष्टता, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नीति मार्गदर्शन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, हाल ही में शुरू किए गए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान', जिसका अर्थ है "स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार", के दौरान लाखों वृद्ध व्यक्तियों, विशेषकर वृद्ध महिलाओं की गैर-संचारी और आयु-संबंधी बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कैंसर के लिए जाँच की गई है।

क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन में, भारत ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल (पीएचसी-एलटीसी) का एकीकरण मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया के सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। भारत ने सहयोग के तीन प्रमुख क्षेत्रों का प्रस्ताव रखाः

पीएचसी-एलटीसी एकीकरण पर ज्ञान साझाकरण और नवाचार के लिए एक क्षेत्रीय मंच की स्थापना;

विभिन्न देशों में वृद्धावस्था और देखभाल करने वाले कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना; और वृद्धों के लिए स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायक तकनीकी नवाचारों और स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देना।

संयुक्त राष्ट्र के स्वस्थ वृद्धावस्था दशक (2021-2030) के साथ भारत के जुड़ाव की पुष्टि करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि वृद्धावस्था को समावेशी विकास और सामाजिक परिवर्तन के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' की कल्पना से प्रेरित होकर, भारत यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वृद्धावस्था सहित जीवन का हर चरण सम्मान, सुरक्षा और देखभाल के साथ जिया जाए।"

निमार्णाधीन रिसॉर्ट में मिट्टी ढहने से मजदूर की दर्दनाक मौत, चार घायल

(जीएनएस)।

पीलीभीतःमाधोटांडा क्षेत्र के निमार्णाधीन रिसॉर्ट में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान बृहस्पतिवार सुबह एक बड़ा हादसा घटित हुआ। खोदाई के समय अचानक मिट्टी का डेरा गड्ढे में काम कर रहे पांच मजदूरों के ऊपर गिर गया। इसमें से मोईन (28) पुत्र नूर मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चार अन्य घायल हो गए।

घायलों में से शादाब की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में दबे मजदूरों को आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया जहां मोईन को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक मोईन दो छोटी बेटियों का पिता था, उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के कारणों की तहकीकात की जा रही है और निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था भी जांच के दायरे में है।

यह घटना स्थानीय लोगों के लिए बड़ा सदमा है और निर्माण कार्यों में सुरक्षा के प्रति सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

इस तरह के हादसों को रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा नियम और उनके कड़ाई से पालन की जरूरत है?

आवासन और शहरी कार्य सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की

योजना के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घर अनुमोदित, 10 लाख से अधिक घरों को मंजूरी महिलाओं और निर्बल वर्गों की आवास आवश्यकताओं को प्राथमिकता

(जीएनएस)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है।

यह निर्णय 15 अक्टूबर 2025 को सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 5वीं बैठक में लिया गया। 1,40,942 घरों की नवीनतम मंजूरियों के साथ, पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के अंतर्गत मंजूरियों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। यह 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

यह बैठक नई दिल्ली के संकल्प भवन में आयोजित की गई और इसमें श्री कुलदीप नारायण, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (जेएसएंडएमडी), एचएफए, एमओएचयूए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पीएमएवाई-यू मिशन निदेशक और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आवास निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, आवासन और शहरी कार्य सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरों में ऑक्यूपेन्सी बढ़ाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आवासन और शहरी कार्य सचिव ने कहा, "योजना के तहत घरों का निर्माण पूरा होने के बाद, यह सुनिश्चित करें कि ऑक्यूपेन्सी में तेजी आए। परियोजनाओं को उन जगहों पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जहां लाभार्थियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सड़कें, सार्वजनिक परिवहन और कनेक्टिविटी उपलब्ध हो।"

संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (जेएसएंडएमडी), एचएफए ने आवासन और शहरी कार्य सचिव को पीएमएवाई-यू 2.0 के कार्यान्वयन की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को घरों के निर्माण कार्य की नींव रखने और उन्हें तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा, "लाभार्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ऋण तक आसान पहुंच या ऋण मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे लाभार्थियों को समय पर अपने घर पूरे करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों को समय पर अपने घर पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और निर्माण प्रक्रिया में विलंब का कारण बनने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए।"

संयुक्त सचिव एवं प्रबंध निदेशक ने यह भी बताया कि प्रगति की निगरानी के लिए पीएमएवाई-यू घरों की नींव रखने और पूरा करने के लिए एक नियमित अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-यू 2.0 का अंगीकार 2025 अभियान जियो-टैगिंग और पीएमएवाई-यू घरों के पूरा होने में तेजी लाने के पीछे प्रेरक बल रहा है।

समिति ने पीएमएवाई-यू 2.0 की प्रगति की भी समीक्षा की और घरों का समय पर निर्माण पूरा करना सुनिश्चित करते हुए योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने की कार्यनीतियों पर चर्चा की।

पीएमएवाई-यू 2.0 पात्र शहरी लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने पर केंद्रित है और समावेशिता को बढ़ावा देती है। यह शहरी गरीबों और समाज के निर्बल वर्गों को किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराकर एक समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान देती है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह योजना परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में मकान स्वीकृत करके महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देती है।

15 अक्टूबर, 2025 को हुई बैठक में, केवल महिलाओं के लिए लगभग 76,976 घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें एकल महिलाएं, विधवाएं और अलग रह रही महिलाएं शामिल हैं, जो महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 13,509 घरों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसजेंडरों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन्हें 7 घर आवंटित किए गए हैं। विभिन्न वंचित समूहों में, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 29,131 घर, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 6,561 घर और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 74,291 घर स्वीकृत किए गए हैं।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत कुल 10 लाख से ज्यादा घरों में से 6.31 लाख से ज्यादा घर केवल महिला लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 70,794 लाभार्थी विधवाएं, अलग रह रही महिलाएं या अविवाहित हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 ने ट्रांसजेंडरों के लिए भी 163 आवास इकाइयां स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को 1.04 लाख घर आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 2.20 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं, 51,181 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी हैं, जबकि 5.35 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना - अर्बन, शहरी भारत के पात्र लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त, हर मौसम में उपयोग के लिए उपयुक्त पक्के घर उपलब्ध कराने हेतु 2015 में शुरू की गई थी। पीएमएवाई-यूके अंतर्गत, 95.51 लाख पक्के घर पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। किफायती आवास की बढ़ती मांग को देखते हुए, इस योजना को नया रूप दिया गया और सितंबर 2024 में पीएमएवाई-यू 2.0 के रूप में लॉन्च किया गया ताकि अतिरिक्त 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत, स्वीकृत घरों की कुल संख्या 122 लाख है।

पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत, एक करोड़ परिवारों को शहरी क्षेत्रों में पक्का घर बनाने या खरीदने के लिए सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के वे परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत लाभ के पात्र हैं। योजना के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की वार्षिक घरेलू आय 9 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

दीपावली से पहले दियूनी बहादुरगंज गांव की गलियां अंधेरे में,ग्रामीण बोले- लाइटें ठीक करो या रोशनी का वादा छोड़ो

(जीएनएस)।

पीलीभीतः मरौरी ब्लॉक के दियूनी बहादुरगंज गांव में दीपावली से पहले अंधेरा छाने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। गांव की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब पड़ी हैं, जिससे शाम होते ही मुख्य चौराहे और गलियां अंधेरे में डूब जाती हैं। खासकर बुजुर्ग और बच्चे इस अंधेरे से खासा प्रभावित हो रहे हैं और उनके आवागमन में परेशानी हो रही है।

ग्रामीण राम चरन, मोहन लाल, ठाकुरदास, ओमकार और दिनेश कुमार ने कई बार संबंधित अधिकारियों और विभागों को शिकायतें भेजीं, लेकिन अभी तक लाइटें ठीक नहीं हो पाई हैं। दीपावली जैसे पर्व के मौके पर गांव में पर्याप्त रोशनी और सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत कराए जाने की मांग की है।

ग्रामीण चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे कड़ी आवाज उठाने पर मजबूर होंगे।

पुराने प्रकरणों पर कार्रवाई न होने से नाराज 14 सभासदों ने केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से की शिकायत

(जीएनएस)।

पीलीभीतः नगर पालिका में लंबे समय से जारी विवाद बुधवार को तब नया मोड़ ले गया जब 14 विरोधी सभासदों ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में दिशा की बैठक खत्म होते ही केंद्रीय राज्यमंत्री एवं पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद को रोक लिया। उन्होंने पूर्व की हुई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई और एक मांग पत्र सौंपा।

शिकायत में बताया गया कि कई वार्डों में पिछले लंबे समय से कोई निर्माण या मरम्मत कार्य नहीं हुआ। इसके बावजूद कुछ वार्डों में बिना बजट पास किए और बोर्ड की सहमति लिए ही निर्माण कार्य जारी हैं, जबकि कई अन्य वार्ड बिना किसी सुधार के पड़े हैं। शासन-प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर नए टेंडर करवाए जाएं ताकि काम सही तरीके से हो सके।

शिकायतकर्ता एहतिशाम वली खां, पुष्पा उपाध्याय, महनाज बेगम, सुनीता सिंह, चैतन्य गंगवार, रत्ना शुक्ला, सुरेश कुमार लोधी, माया देवी, शिवम, शिखा वर्मा, राजेंद्र कुमार सहित कुल 14 सभासद हैं।

यह मामला नगर पालिका के अंदर चल रही राजनीतिक रार को एक बार फिर उजागर करता है और तय समय में पूर्व शिकायतों का निपटारा न होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।

दो बाइकों में आमने-सामने से हुई जोरदार टक्कर,टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल

ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को भिजवाया अस्पताल।

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर। दो बाइकों में आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रुप से घायल हो गए।

जानकारी के मुताबिक थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के जगतपुर गांव के पास गुरुवार दोपहर सड़क हादसा हुआ। नहर के पास दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर में मुरादपुर निवासी अभिषेक शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। अभिषेक अपनी दो बहनों को जोगराजपुर सेवाराम नत्थूलाल इंटर कॉलेज से लेने जा रहा था, तभी सामने से आई बाइक (चालक विनय शुक्ला) से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह सड़क से दूर जा गिरा और उसका पैर टूट गया। हादसे के बाद अफरातफरी मच गई, ग्रामीणों ने पुलिस व एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे के कारण सड़क पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।

थाना सेहरामऊ प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल भिजवाया, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।

थाना गोमती नगर पुलिस और क्राइम टीम प्रभारी शिवानंद मिश्रा की टीम को मिली बड़ी कामयाबी

(जीएनएस)।

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट अमरेन्द्र कुमार सेंगर के दिशा-निर्देशन में काम कर रही गोमती नगर पुलिस और मड़ियांव थाना प्रभारी के तेजतर्रार क्राइम प्रभारी शिवानंद मिश्रा को लगातार मिल रही सफलताएं आपको बताते चलें चार पहिया वाहन की लूट व चोरी गिरोह के चार आरोपियों को कमिश्नरेट पुलिस ने किया गिरफ्तार पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे व चोरी किए गए 2 चार पहिया वाहन भी बरामद किए बरामद की गई गाड़ियों में एक मारुती स्विफ्ट डिजायर और एक इग्निस कार शामिल है कुछ दिनों पहले मारुती स्विफ्ट डिजायर कार की हुई थी लूट बीते दिनों

अम्बेडकर पार्क के सामने से चोरों ने एक कार की थी चोरी शिवानंद मिश्रा की क्राइम टीम व गोमती नगर पुलिस ने मात्र दो दिन में खुलासा करते हुए आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे

सलोन नगर में नए रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ

(जीएनएस)।

लखनऊ। रायबरेली में नगर पंचायत सलोंनं के एसडीएम कोर्ट के पास गैलेक्सी रेस्टोरेंट , व आइसक्रीम पार्लर का शुभारंभ फीता काट के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी कशीम सिद्दीकी के द्वारा किया गया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद नईम, सैयद आले अहमद, मोहम्मद नदीम सिद्दीकी, अमजद भाई, यूको बैंक के शाखा प्रबंधक शशांक जायसवाल, समेत नगर के दर्जनों संभ्रांत नागरिक, दुकानदार, व्यापारी मौजूद रहे। इस रेस्टोरेंट में एसी , नान एसी फैमिली रेस्टोरेंट के भी व्यवस्था शुरू की गई। इस रेस्टोरेंट के खुलने से नगर के व आसपास के लोगों को परिवार के साथ बेहतर व्यवस्था मुहैया होगी। लोग इसमें अपने परिवार व बच्चों के साथ भी शिरकत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में

आइसक्रीम पार्लर भी उपलब्ध है।

प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 29वीं बोर्ड बैठक संपन्न

प्रयागराज 16 अक्टूबर

मण्डलायुक्त श्रीमती सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरूवार को आयुक्त कार्यालय स्थित गाँधी सभागार में प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 29वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया।

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रारूपित वित्तीय विवरणों को बोर्ड बैठक में अनुमोदित किया गया तथा मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

* बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चल रही प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में

मंडलायुक्त द्वारा स्मार्ट सिटी के तहत जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं उन्हें सस्टेनेबल रखने के लिए इन प्रोजेक्टों को रेवन्यू जेनेरेटिंग बनाने के आवश्यक प्रबंध करने के लिए कहा गया है।

* मण्डलायुक्त ने पीडीए द्वारा स्थापित बस शेल्टरों की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा जिन बस शेल्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें हस्तांतरित करने के निर्देश दिए।

* बैठक में बोट क्लब स्थित फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट एवं नौकायन सेवा, जिसने महाकुंभ 2025 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। उक्त परियोजना पूर्व में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी, इसके संचालन के विस्तार हेतु एक नवीन निविदा जारी की गई है, जिससे नगर में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध, गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित बजट के भीतर पूरी की जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री अमित पाल शर्मा, नगर आयुक्त श्री साई तेजा एवं स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार युवक ने साइकिल सवार युवक को रौंदा

(जीएनएस)।

पीलीभीत पूरनपुर।थाना सेहरामऊ क्षेत्र के ग्राम पिपरा मुजफ्ता निवासी विपिन शर्मा मुरादपुर से अपने घर जा रहे थे तभी रास्ते में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और सुल्तानपुर चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई।

घायल युवक को 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया है ।उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद टक्कर मारकर फरार हुए मोटरसाइकिल चालक का मोबाइल और चश्मा हादसे के स्थल पर पुलिस को मिले हैं,जिन्हें उन्होंने कब्जे में लेकर चालक की पहचान पूछताछ की जा रही है ।पुलिस ने मामला दर्ज कर इस घटना की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

कैसरबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता चोरी की स्कूटी के साथ दो शातिर चोरों को धर दबोचा

(जीएनएस)।

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट अमरेन्द्र कुमार सेंगर के दिशा-निर्देशन में काम कर रही थाना कैसरबाग पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बार फिर सक्रियता का परिचय दिया है। पुलिस कमिश्नर लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) व अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग तथा प्रभारी निरीक्षक कैसरबाग के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने दोनों अभियुक्तों को रौशनदौला लाइब्रेरी के पीछे कचहरी जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त सुजान खान पुत्र इमरान खान निवासी 446/27 घासमंडी, थाना ठाकुरगंज, लखनऊ (उम्र लगभग 29 वर्ष) और मोहम्मद जुनैद पुत्र मोहम्मद जावेद निवासी कच्ची ढाल, फैजुल्लागंज, थाना मड़ियाव, लखनऊ (उम्र लगभग 35 वर्ष) है पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 को आदर्श कुमार कश्यप की तहरीर पर थाना कैसरबाग में मुकदमा अपराध संख्या 179/2025 अंतर्गत धारा 303(2) इठर पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते

हुए पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी की वारदात को कबूल किया और माफी मांगी। पकड़े गये चोरों के पास से बरामद हुई एक चोरी की सफेद रंग की स्कूटी (नंबर झ्र वढ32 लऊ 9723) बरामद की गई। गिरफ्तारी स्थल व समय रौशनदौला लाइब्रेरी के पीछे, कचहरी जाने वाले रोड की ओर, दिनांक 15/10/2025, समयः 16:00 बजे। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 पवन मौर्य, उ0नि0 विशाल सिंह, उ0नि0 पीर मोहम्मद कांस्टेबल जिमेन्द्र सिंह, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल आलोक कुमार ने अभियुक्तों को विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।